

भारत सरकार की जनजातीय कार्य "मंत्रालय" की योजना  
अंतर्गत अशासकीय संस्थाओं को अनुदान

**उद्देश्य :-**

1. अनुसूचित जन जाति संवर्ग का शैक्षणिक उत्थान ।
2. अनुसूचित जनजाति संवर्ग का आर्थिक उत्थान ।

**प्रावधान :-**

पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थाओं के संचालन पर भारत सरकार से शतप्रतिशत अनुदान का प्रावधान ।

**कौन लाभ ले सकता है :-**

म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन पंजीबद्ध अशासकीय संस्था / रजिस्ट्रेशन 3 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है ।

**योजना का लाभ कैसे ले सकते है :-**

1. किससे संपर्क करें – कार्यालय कलेक्टर / सहायक आयुक्त, आदि.वि.डिण्डौरी
2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें – कार्या.सहायक आयुक्त, आदि.वि. डिण्डौरी ।
3. आवेदन करने का तरीका :- निर्धारित प्रारूप में लिखित आवेदन सीधे प्रस्तुत करें
4. आवश्यक दस्तावेज :-

1. निर्धारित आवेदन पत्र
2. प्रस्तावित प्रोजेक्ट प्रोफाइल
3. विगत तीन वर्ष का लेखा प्रतिवेदन
4. विगत तीन वर्ष का प्रगति प्रतिवेदन

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास डिण्डौरी  
जिला डिण्डौरी